

प्रश्न: भारत के लिए 'पड़ोस प्रथम' (Neighbourhood First) नीति क्यों अनिवार्य है?

परिचय

किसी भी देश की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ उसका अपने पड़ोसियों के साथ संबंध होता है। भारत के संदर्भ में, 'पड़ोस प्रथम' (Neighbourhood First) नीति का अर्थ है अपने तात्कालिक पड़ोसियों (जैसे- नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान) के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, "हम मित्र बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं।" इसी विचार को केंद्र में रखकर वर्तमान मोदी सरकार ने भी इस नीति को और अधिक सक्रिय बनाया है।

भारत के लिए यह नीति निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य है:

1. क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता (Regional Security)

भारत की सुरक्षा सीधे तौर पर उसके पड़ोसियों की स्थिरता से जुड़ी है। यदि पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता या गृहयुद्ध जैसे हालात होते हैं, तो उसका सीधा असर भारत की सीमावर्ती सुरक्षा पर पड़ता है।

- **उदाहरण:** म्यांमार में सैन्य तख्तापलट या अफगानिस्तान में अस्थिरता भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां पैदा करती हैं।

2. चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना (Countering China)

चीन अपनी 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) और 'स्ट्रिंग ऑफ पर्स' (String of Pearls) नीति के माध्यम से भारत के पड़ोसियों (जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल) में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सामरिक संबंध मजबूत रखे ताकि चीन के प्रभुत्व को कम किया जा सके।

3. आर्थिक एकीकरण और कनेक्टिविटी (Economic Connectivity)

दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है। भारत के आर्थिक विकास के लिए पड़ोसियों के साथ व्यापार और बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है।

- **BBIN** (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) और **BIMSTEC** जैसे संगठन इसी दिशा में

कार्य कर रहे हैं ताकि सड़क, रेल और जलमार्ग के जरिए व्यापार सुगम हो सके।

4. आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद पर नियंत्रण (Internal Security)

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए म्यांमार और बांग्लादेश का सहयोग अनिवार्य है। सीमा पार से होने वाले आतंकवाद, मानव तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए 'पड़ोस प्रथम' नीति सुरक्षा कवच का काम करती है।

5. वैश्विक आकांक्षाएं और नेतृत्व (Global Leadership)

यदि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता या एक वैश्विक महाशक्ति (Global Power) बनना चाहता है, तो उसे पहले अपने क्षेत्र (South Asia) में एक सर्वमान्य नेता के रूप में खुद को स्थापित करना होगा। एक अस्थिर पड़ोस भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित करता है।

6. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध (Cultural Ties)

भारत का अपने पड़ोसियों के साथ सदियों पुराना भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है (जैसे 'रोटी-बेटी का रिश्ता' नेपाल के साथ)। इन संबंधों को बनाए रखना भारत की 'सॉफ्ट पावर' (Soft Power) के लिए अनिवार्य है।

‘पड़ोस प्रथम’ नीति के समक्ष मुख्य चुनौतियां

चुनौती	विवरण
पाकिस्तान कारक	प्रायोजित आतंकवाद और कश्मीर मुद्दा संबंधों में सबसे बड़ी बाधा है।
चीन का कर्ज जाल	चीन द्वारा पड़ोसियों को भारी कर्ज देकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना।
घरेलू राजनीति	पड़ोसी देशों (जैसे बांग्लादेश या श्रीलंका) की आंतरिक राजनीति में भारत-विरोधी भावनाओं का उभरना।

परियोजनाओं में देरी	भारत द्वारा घोषित ढांचागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाली देरी।
---------------------	---

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारत के लिए 'पड़ोस प्रथम' नीति केवल एक कूटनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि एक भौगोलिक और सामरिक मजबूरी है। भारत का 'विश्व गुरु' बनने का सपना तभी साकार हो सकता है जब उसका पड़ोस शांतिपूर्ण, समृद्ध और सहयोगी हो। भारत को चाहिए कि वह 'बड़े भाई' (Big Brother) की छवि त्याग कर एक 'बड़े मददगार' (Big Facilitator) के रूप में उभरे।